# राजस्थान की धरा शौर्य, आस्था व भक्ति की त्रिवेणी - भजनलाल

## मुख्यमंत्री ने बालोतरा के कनाना श्रीमठ में आयोजित श्री ललिता महायज्ञ की पूर्णाहुति में भाग लिया

बालोतरा, 24 मार्च (नि.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजनीति हो या अन्य कार्य, धर्म आवश्यक है, धर्म के अभाव में कोई भी कार्य ठीक से नहीं हो सकता। सनातन परम्परा हमें धर्म पर चलते हुए सामाजिक एकता के साथ आगे बढ़ने

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले एक वर्ष से चल रहे श्री ललिता महायज्ञ की पूर्णाहुति कार्यक्रम में देश भर से आए प्रमुख संत-महंतों का दुपट्टा ओढ़ाकर एवं श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। महंत परशुराम गिरी महाराज ने मुख्यमंत्री को श्रीयंत्र भेंट कर अभिनंदन किया।**

की प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की धरा शौर्य, आस्था और भक्ति की त्रिवेणी है, जहां साधु-संतों के आशीर्वाद से सनातन संस्कृति का पुनर्जागरण हो रहा है।

शर्मा मंगलवार को बालोतरा के कनाना श्रीमठ में आयोजित श्री ललिता महायज्ञ की पूर्णाहुति एवं मां सरस्वती

*मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को बालोतरा के कनाना श्रीमठ में आयोजित श्रीललिता महायज्ञ की पूर्णाहुति एवं मां सरस्वती मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लिया।*

मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाजिक एकता को सुदृढ़ करने के साथ ही, आने वाली पीढ़ी को विरासत से जोड़ते हैं।

मुख्यमंत्री ने बालोतरा के धार्मिक महत्व को बताते हुए कहा कि यहां के तीर्थ स्थल हमारी गौरवशाली संस्कृति के सजग प्रहरी हैं। वहीं, कनाना मठ की पवित्र भूमि अलौकिक ऊर्जा का संचार करती है।

देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि मंदिरों के विकास और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

कार्यक्रम के दौरान, कनाना मठ के महंत परशुराम गिरि महाराज ने मुख्यमंत्री का अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन अखण्ड भारत और सनातन संस्कृति की पहचान हैं।

इससे पहले, मुख्यमंत्री ने पिछले एक वर्ष से चल रहे श्री ललिता महायज्ञ में पूर्णाहुति दी। साथ ही, कार्यक्रम में देशभर से आए प्रमुख संत-महंतों का दुपट्टा ओढ़ाकर एवं श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। महंत परशुराम गिरि महाराज ने मुख्यमंत्री को श्री यंत्र भेंट कर उनका अभिनंदन किया।

इस दौरान, उद्योग एवं वाणिज्य राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के.के. विश्नोई, विधायक हमीर सिंह भायल, महंत प्रतापपुरी, आदूराम मेघवाल,

# दिल्ली वालों को दो फ्री सिलैण्डर मिलेंगे

-जाल खंबाता -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 मार्च। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को 2026-27 के लिए दिल्ली का बजट पेश किया। इस बजट में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च और पर्यावरण पर जोर के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई है।

- **मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली का 2026-27 का बजट पेश करते हुए घोषणा की।**

हालांकि रेखा गुप्ता ने पिछली सरकार की "फ्रीबी संस्कृति" की खूब आलोचना की, लेकिन साथ ही, बजट में 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने के लिए 260 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया। 1,03,700 करोड़ रुपये का यह बजट राजधानी के सबसे बड़े बजटों में से एक है। सरकार ने इसे ग्रीन बजट का नाम दिया है, हालांकि इसमें सड़कों, शहरी विकास और नागरिक सुविधाओं पर भी बड़ा खर्च रखा गया है। पिछले साल उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था।

# 'हिंदू, सिख, बौद्ध के अलावा अन्य धर्म अपनाने पर एससी का दर्जा नहीं मिलेगा'

## सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट को लेकर मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया

नई दिल्ली, 24 मार्च। सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट को लेकर मंगलवार को एक बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने फैसले में कहा कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को अपनाता है उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता।

कोर्ट ने आगे कहा कि किसी अन्य धर्म अपनाने पर अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत और पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जस्टिस पी. के. मिश्रा और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की पीठ ने फैसला सुनाया कि किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण करने से अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो जाता है। कोर्ट ने कहा कि संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 में यह बात साफ कर दी गई थी और इस आदेश के तहत लगाई गई रोक पूरी तरह से लागू होती है। कोर्ट

- **सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 1950 के आदेश के क्लॉज 3 में बताए गए धर्मों के अलावा किसी अन्य धर्म को अपनाने से अनुसूचित जाति की दर्जा तुरंत खत्म हो जाता है।**

ने साफ किया कि 1950 के आदेश के क्लॉज 3 में बताए गए धर्मों के अलावा, किसी और धर्म को अपनाने पर, जन्म की स्थिति चाहे जो भी हो, अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत खत्म हो जाता है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि खंड 3 के तहत, कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाता है, वह संविधान या संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत किसी भी वैधानिक लाभ, सुरक्षा, आरक्षण या अधिकार का दावा नहीं कर सकता और न ही उसे ये लाभ दिए जा सकते हैं। यह रोक पूरी तरह से लागू होती है और इसमें कोई अपवाद नहीं है। कोई भी व्यक्ति एक ही समय पर खंड 3 में बताई गई जाति के अलावा, किसी अन्य धर्म को मानने और उसका पालन करने के साथ-साथ अनुसूचित जाति की सदस्यता का दावा नहीं कर सकता।"

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के पहले के उस फैसले को सही ठहराया, जिसमें कहा गया था कि जो लोग ईसाई धर्म अपना लेते हैं और सक्रिय रूप से उसका पालन करते हैं, वे अपना अनुसूचित जाति (एससी) का दर्जा बरकरार नहीं रख सकते।

# हरीश राणा ने ली अंतिम सांस

नई दिल्ली, 24 मार्च। देश में निष्क्रिय इच्छामृत्यु (पैसिव यूथेनेशिया) की अनुमति पाने वाले पहले व्यक्ति हरीश राणा का मंगलवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में निधन हो गया। एम्स ने जारी एक बयान में कहा कि हरीश राणा ने मंगलवार को शाम 4.10 मिनट पर अंतिम सांसें ली। वे समर्पित चिकित्सकों की टीम की देखरेख में थे और उन्हें ऑन्को-एनेस्थीसिया विभागाध्यक्ष, डॉ. (प्रो.) सीमा मिश्रा के नेतृत्व में पैलिएटिव ऑन्कोलॉजी यूनिट (आईआरसीएच) में भर्ती कराया गया था। एम्स ने हरीश राणा के परिवार और प्रियजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। हरीश राणा का मामला देश में गरिमा के साथ मृत्यु के अधिकार (राइट टू डाई विद डिग्निटी) पर एक ऐतिहासिक निर्णय माना गया था। हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को विशेष अनुमति देते हुए उनकी सम्मानपूर्वक मृत्यु के लिए एम्स प्रबंधन को जीवनरक्षक उपचार हटाने (लाइफ सपोर्ट विदड्राल) की इजाजत दी थी। चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी में बीटेक की पढ़ाई कर रहे हरीश राणा 20 अगस्त 2013 को हॉस्टल की चौथी मंजिल से नीचे गिर गए थे।

# अमेरिका व ईरान ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वित्तीय और तेल बाजार को प्रभावित करने और उस संकट से निकलने के लिए किया जा रहा है, जिसमें अमेरिका और इज़राइल फंसे हुए हैं।"

फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारी पर्दे के पीछे तेहरान और ट्रंप टीम के दूतों, विटकॉफ और जारेड कुशनर, के बीच बातचीत करा रहे थे। साथ ही, प्रधानमंत्री शरीफ ने युद्ध शुरू होने के बाद से कई बार पेज़ेश्कियन से बात की है।

सोमवार को हुई बातचीत के बारे में जारी एक बयान में पाकिस्तान ने कहा, "प्रधानमंत्री ने ईरानी राष्ट्रपति को पाकिस्तान के कूटनीतिक प्रयासों की जानकारी दी और आश्वासन दिया कि पाकिस्तान शांति स्थापित करने में रचनात्मक भूमिका निभाता रहेगा।"

पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कथित रुप से पिछले सप्ताह रियाद में हुई बैठक में अरब देशों के प्रतिनिधियों से कहा कि इस्लामाबाद अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कर रहा है, हालांकि उन्होंने ज्यादा जानकारी नहीं दी। एक राजनयिक ने फायनैंशियल टाइम्स को बताया कि पाकिस्तान ही इस मध्यस्थता प्रयास का नेतृत्व कर रहा है।

पाकिस्तान, जहाँ कोई भी अमेरिकी सैन्य अड्ड नहीं है, इस क्षेत्र के उन गिने-चुने अमेरिकी सहयोगियों में से एक है, जो तेहरान की मिसाइलों और ड्रोन हमलों से सुरक्षित रहे हैं। इससे पाकिस्तान को ईरान और यू.एस. के बीच एक निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिली है। पाकिस्तान में ईरान के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिया मुस्लिम आबादी है और उसके खाड़ी देशों, खासकर सऊदी अरब, के साथ भी अच्छे संबंध हैं। पिछले साल दोनों देशों के बीच आपसी रक्षा समझौता भी हुआ था।

ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह मोजतबा खामेनेई ने पिछले सप्ताह ईरानी नववर्ष की शुरुआत पर जारी एक संदेश में पाकिस्तान का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि उन्हें पाकिस्तान की जनता से खास लगाव है।

यह अभी स्पष्ट नहीं है कि पाकिस्तान की मध्यस्थता की कोशिश और ट्रंप द्वारा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर ईरान के पावर ग्रिड पर बमबारी करने की अपनी धमकी टालने की घोषणा का आपस में कोई संबंध है या नहीं। लेकिन एक यूरोपीय अधिकारी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच सीधे बातचीत नहीं हुई, बल्कि मिस्र, पाकिस्तान और खाड़ी देश संदेशों का आदान-प्रदान कर रहे हैं।

तुर्की, जो युद्ध से पहले भी मध्यस्थता में शामिल था, अब भी ईरानी अधिकारियों और ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ से बातचीत कर रहा है, ताकि अस्थायी युद्धविराम कराया जा सके और बातचीत का रास्ता खोला जा सके।

फायनैंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने अपने तुर्की समकक्ष हाकान फिदान से बातचीत की, जबकि, मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलअत्ती ने रविवार को ईरान, पाकिस्तान, विटकॉफ और कतर के विदेश मंत्री से बात की।

# 'वॉशिंगटन से संदेश आया, ट्रंप समझौता चाहते हैं'

## ईरान के विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी

वॉशिंगटन/तेहरान, 24 मार्च। पिछले माह 28 फरवरी से छिड़े युद्ध के बीच तेहरान को मध्यस्थों के जरिए वॉशिंगटन से संदेश मिला है। यह संदेश अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की संभावित शुरुआत हो सकता है। ईरान के विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। इससे पहले राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने संकेत दिया था कि दोनों देशों के बीच समझौता संभव है।

सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के

- **ज्ञातव्य है कि इससे पहले तक ट्रंप के ईरान से वार्ता चलने के दावे का ईरान ने ही खंडन किया था।**

अनुसार, ईरानी अधिकारी ने कहा, "हमें मध्यस्थों के मार्फत अमेरिका से कुछ सार्थक संदेश मिले हैं। हम उनकी समीक्षा कर रहे हैं।" इससे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि अमेरिका और ईरान के बीच दुश्मनी को पूरी तरह से खत्म करने के संबंध में बहुत अच्छी और सार्थक बातचीत हुई है।"

उन्होंने इसके बाद पत्रकारों से कहा कि दोनों पक्षों के बीच लगभग 15 मुद्दों पर सहमति बनी है। इसके बाद ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि "वे शांति चाहते हैं।" राष्ट्रपति ट्रंप ने सप्ताहांत में ईरान को दी गई धमकी भी वापस ले ली। उन्होंने कहा था कि 48 घंटे के अंदर अगर ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य को नहीं खोलता तो उसके बिजली संयंत्रों पर हमला किया जाएगा।

ईरान के विदेश मंत्रालय ने शुरू में इस बात से इनकार किया था कि दोनों देशों के बीच कोई बातचीत चल रही है। अब ट्रंप के बयानों से यह उम्मीद जगी कि सैन्य संघर्ष अब खत्म होने के करीब हो सकता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि ईरान और अमेरिका के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं हैं। बावजूद इसके, ऐतिहासिक रूप से वे एक-दूसरे से अप्रत्यक्ष रूप से ही बातचीत कर रहे हैं।

# सऊदी अरब चाहता है ईरान पर हमले जारी रहें

वॉशिंगटन, 24 मार्च। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रम्प से कहा है कि ईरान के खिलाफ जंग जारी रखी जाए। उनके मुताबिक, यह मिडिल ईस्ट को बदलने का एक बड़ा मौका है। यह दावा न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया है।

अखबार ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से इसकी जानकारी दी है। क्राउन प्रिंस ने पिछले हफ्ते ट्रम्प से बातचीत की थी और कहा था कि अमेरिका को ईरान की मौजूदा सरकार को खत्म कर देना चाहिए।

उनका मानना है कि ईरान खाड़ी देशों के लिए लंबे समय का खतरा है और इस खतरे को सिर्फ शासन बदलकर ही खत्म किया जा सकता है।

लेकिन सऊदी सरकार ने इन रिपोर्ट्स को खारिज किया है। उसने

- **वहां के क्राउन प्रिंस ने पिछले सप्ताह ट्रंप से कहा कि ईरान की मौजूदा सरकार को खत्म कर देना चाहिए।**

कहा कि सऊदी अरब हमेशा इस संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान चाहता है और उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है।

इस बीच, सऊदी और अमेरिकी अधिकारियों को चिंता है कि अगर युद्ध लंबा चला, तो ईरान सऊदी तेल ठिकानों पर बड़े हमले कर सकता है और अमेरिका एक लंबी लड़ाई में फंस सकता है।

# 'धनखड़ के ईस्तीफे ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

"अनलाइकली पैराडाइज़" के अपडेटेड अंग्रेजी संस्करण में राउत ने लिखा है कि धनखड़ को जांच एजेंसियों की धमकी देकर इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि एनडीए सरकार को उनके "स्वतंत्र फैसले" पसंद नहीं थे। इस पुस्तक के विमोचन समारोह में पूर्व केन्द्रीय मंत्री कपिल सिब्बल, आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविन्द केजरीवाल और तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ'ब्रायन मौजूद थे।

सोमवार को नई दिल्ली में विमोचित इस पुस्तक में राउत ने दावा किया कि ईडी ने धनखड़ के खिलाफ उनकी संपत्ति के सौदों और विदेशी खातों में भेजी गई रकम को लेकर एक फाइल तैयार की थी। राउत ने लिखा: "अफवाहें फैली थीं कि धनखड़ और उनकी पत्नी ने जयपुर स्थित अपना घर बेच दिया और उसकी कुछ राशि विदेश भेज दी। ईडी, जो उनकी गतिविधियों पर बारीक नज़र रख रही थी, ने कथित तौर पर पूर्व उपराष्ट्रपति के खिलाफ आरोप तय करने के लिए एक फाइल तैयार की। इस काम में अन्य जाँच एजेंसियां भी शामिल थीं। जब मोदी सरकार के खिलाफ धनखड़ के स्वतंत्र राजनीतिक कदमों की चर्चा होने लगी, तो ईडी ने कथित तौर पर यह फाइल उनके सामने

- **राउत ने आरोप लगाया कि सरकार इसी प्रकार से देश के राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ भी ईडी से फाइल्स तैयार करवाती है।**

रखी और इस्तीफा देने के लिए दबाव बनाया।" राउत ने यहाँ तक आरोप लगाये हैं कि ईडी का प्रभाव न्यायाधीशों और यहां तक कि भारत के राष्ट्रपति के कामकाज तक फैला हुआ है।

धनखड़ के इस्तीफे के तुरंत बाद, राजनीतिक हलकों में यह चर्चा थी कि उनके अचानक पद छोड़ने का तत्काल कारण दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने से संबंधित उनकी कार्यवाही थी। धनखड़ ने यह कदम विपक्ष द्वारा लाए गए प्रस्ताव के सिलसिले में उठाया था। ज्ञातव्य है कि मार्च 2025 में उनके आवास से बड़ी मात्रा में अधजली नकदी मिलने के बाद, जस्टिस वर्मा विवादों में आ गए थे।

# ईरान के शीर्ष ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ढुलमुल हैं। कुछ मौकों पर उन्होंने हमलों को ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए जरूरी बताया, वहीं कई अन्य जगहों पर इसे क्षेत्रीय युद्ध को टालने के लिए पूर्व निर्धारित कदम बताया। इस बदलते रुख ने आलोचना को जन्म दिया है कि प्रशासन के पास स्पष्ट रणनीतिक दृष्टिकोण की कमी है।

आंतरिक मतभेद के संकेत देते हुए, ट्रंप ने यह भी खुलासा किया कि उपराष्ट्रपति जेडी वैंस सैन्य कार्रवाई के खास समर्थक नहीं थे, हालांकि वेंस ने सार्वजनिक रूप से कोई विरोध नहीं जताया है। यह बयान प्रशासन के भीतर संभावित मतभेदों की ओर इशारा करता है, जबकि वॉशिंगटन बाहर से एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है।

हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया कितनी व्यापक और घातक हो सकती है, इसका सही आकलन नहीं हुआ। ट्रंप ने स्वीकार किया कि अमेरिका ने यह उम्मीद नहीं की थी कि तेहरान खाड़ी देशों पर जवाबी हमले कर देगा। इन हमलों ने संघर्ष के भौगोलिक दायरे को बढ़ा दिया है और व्यापक क्षेत्रीय युद्ध की आशंका को जन्म दिया है। ईरान के बाद के कदम, जिनमें होर्मुज़ स्ट्रेट में आवाजाही को प्रभावी रूप से बाधित करना शामिल है, ने वैश्विक ऊर्जा बाजार और व्यापार मार्गों को झकझोर दिया है।

ट्रंप ने अपने रुख में उल्लेखनीय बदलाव करते हुए सोमवार को ईरान के बिजली संयंत्रों और ऊर्जा ढांचे हमला करने में अस्थायी विराम की घोषणा की। ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किए गए बयान में उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन ने ऐसे सभी सैन्य हमलों को पांच दिनों के लिए टालने का फैसला किया है, जो तेहरान के साथ चल रही वार्ताओं में प्रगति पर निर्भर करेगा।

ट्रंप ने कहा, "मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले दो दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच बहुत अच्छी और सकारात्मक वार्ता हुई, जो मध्य पूर्व में हमारी शत्रुता के पूर्ण समाधान की दिशा में एक कदम है। उन्होंने आगे कहा कि यह विराम बातचीत के "रचनात्मक" माहौल के आधार पर लिया गया है, जिसके पूरे सप्ताह जारी रहने की उम्मीद है।

यह घोषणा एक संभावित कूटनीतिक अवसर की ओर संकेत करती है, हालांकि संघर्ष अभी भी अस्थिर बना हुआ है। यह स्पष्ट नहीं है कि यह पांच दिन का समय स्थायी तनाव-नियंत्रण की ओर बढेगा या या सिर्फ एक सामरिक विराम साबित होगा।

संघर्ष की शुरुआत 28 फरवरी को अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरानी ठिकानों पर किए गए हवाई हमलों से हुई थी, जिसमें कथित तौर पर कई वरिष्ठ अधिकारियों की मौत हुई थी। इसके बाद स्थिति तेजी से बिगड़ती गई, जिसमें जवाबी कार्रवाई, समुद्री व्यापार में बाधाएं और पूरे क्षेत्र में नागरिक व सैन्य हताहतों की संख्या में वृद्धि शामिल है।

फिलहाल, ट्रंप का नैरेटिव को फिर से संतुलित करने का प्रयास, प्रशासन के भीतर जिम्मेदारी बांटने और वार्ता के लिए खुलापन दिखाने के जरिए, घरेलू दर्शकों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भी ध्यान में रखकर किया गया प्रतीत होता है। लेकिन जैसे-जैसे संघर्ष जारी है और इसके प्रभाव वैश्विक बाजारों तक फैल रहे हैं, अमेरिकी रणनीति की विश्वसनीयता और स्पष्टता पर सवाल बने रहने की संभावना है।

# ग्रेजुएट जवानों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

थी, यानी उन्हें अधिकारी बनने में कुल चार साल लगते थे। हालांकि, 12वीं पास जवानों के लिए इस व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

# सोनिया गांधी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

डॉक्टरों की एक विशेष टीम उनकी देखरेख कर रही है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में उनकी सेहत को लेकर चिंता का माहौल है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।

# उदयपुर आईजी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

संरक्षक कुकी बाई को भी आरोपी बनाकर मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बाद 17 नवंबर 2025 को गोपाललाल पर भी ज़मीन हड़पने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया।

एफ.आई.आर. में गोपाललाल भील का आरोप है कि उसके द्वारा खरीदी हुई बेशकीमती जमीन को जबरन बिकवाने के लिए हेमंत शर्मा ने उसे यूनिवर्सिटी गेस्ट हाऊस में बंधक बनाकर डराया-धमकाया। वहां अभियुक्त हेमंत शर्मा ने उसे जान से मारने की धमकियां दीं, जिन खातेदारों से मैने जमीन खरीदी थी, उन्हें भी पिण्डवाडा से हैडकांस्टेबल नीतेश मेनारिया और सुमेर झाकड़ और उनके पुलिस जाब्ते ने जबरदस्ती उठाकर यूनिवर्सिटी गेस्ट हाऊस में बंधक बना लिया। इसके बाद 3 दिसंबर 2025 को आरोपी हेमंत शर्मा के वकील ने उसके द्वारा खरीदी हुई जमीन को बेचने के एग्रीमेंट पर डरा- धमकाकर हस्ताक्षर करवा लिए।

एफ.आई.आर. में गोपाललाल भील का कहना है कि उसने जिस ज़मीन को 2.09 करोड़ रुपए में खरीदा था, उसकी जबरन हेमंत शर्मा के डमी खातेदार गुमानाराम के नाम पर रजिस्ट्री करवा दी गई। आरोप है कि उदयपुर पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) गौरव श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक राजेश यादव, सुखेर थानाधिकारी रविन्द्र चारण, हैडकांस्टेबल नीतेश मेनारिया और कांस्टेबल सुमेर झाकड़ समेत, अन्य पुलिसकर्मियों ने हेमंत शर्मा का पूरा साथ दिया।

# ट्रंप ने मोदी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ईरान युद्ध को सुलझाने के प्रयासों में खुद को प्रमुख मध्यस्थ के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है।

यह बातचीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 28 फरवरी को ईरान और अमेरिका-इज़रायल गठबंधन के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद, दोनों नेताओं के बीच यह पहली सीधी बातचीत है। बढ़ते तनाव के बीच, इसे एक नए कूटनीतिक संवाद की शुरुआत माना जा रहा है।

# पश्चिम एशिया संकट पर आज सर्वदलीय बैठक

## केन्द्र सरकार की पहल पर संसद परिसर में बैठक आयोजित होगी

नई दिल्ली, 24 मार्च। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध को लेकर केन्द्र सरकार ने बुधवार शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह बैठक संसदीय सौंध (पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी) में होगी। बैठक में सभी दलों के सदन के नेताओं को आमंत्रित किया जाता है। इस बैठक में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के भारत पर पड़ने वाले असर पर बात होगी। साथ ही, घरेलू गैस (एलपीजी) की आपूर्ति और अस्थिर बाजार स्थितियों पर भी सरकार विपक्ष के साथ चर्चा करेगी। लेकिन सरकार की मुखर आलोचना करने वाले विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बैठक में सम्मिलित होने की उम्मीत कम ही है। राहुल गांधी ने स्वयं मीडिया से बातचीत में कहा है कि वे

- **विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस, पश्चिम एशिया संकट से निपटने के मुद्दे पर सरकार के मुखर आलोचक हैं पर चर्चा है कि राहुल गांधी बैठक में शामिल नहीं होंगे।**

पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार केरल जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे पर सरकार के रुख की आलोचना करते हुए जल्द से जल्द सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की थी। मंगलवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पश्चिम एशिया संघर्ष से निपटने के सरकार के तरीके पर निशाना साधा।

राज्यसभा में सांसद जॉन ब्रिटास ने 2003 के उस संसदीय प्रस्ताव का हवाला दिया, जिसमें इराक युद्ध की निंदा की गई थी, और सरकार से ईरान के मामले में भी इसी तरह का रुख अपनाने की अपील की। इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को राज्यसभा में भारत की ऊर्जा सुरक्षा और पश्चिम एशिया संघर्ष के व्यापक प्रभावों पर बात की। उन्होंने सभी राज्यों से केन्द्र के साथ मिलकर काम करने की बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसे कठिन समय में यह जरूरी है कि संसद का उच्च सदन शांति और संवाद का एकजुट संदेश दे।

# 'भाजपा आई तो ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बंगालियों ने मछली को नहीं चुना, बल्कि भौगोलिक स्थिति ने यह तय किया कि बंगाली मछली खाएं। आज का बंगाल दुनिया के सबसे बड़े नदी डेल्टा में स्थित है, जहां विभिन्न प्रकार की मछलियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। स्वाभाविक रूप से मछली भोजन का हिस्सा बन गई और चावल, जो इस क्षेत्र की मुख्य फसल है, के साथ इसका मेल हुआ। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर यह संयोजन यहां की नम जलवायु के अनुकूल है और एक मुख्य आहार है। लेकिन मछली की भूमिका सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है।

बंगाल की संस्कृति में मछली को शुभ माना जाता है और यह शादी-विवाह व अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक आयोजनों का हिस्सा होती है। बंगाली कैलेंडर का सबसे बड़ा उत्सव, दुर्गा पूजा, भी मांसाहारी व्यंजनों के बिना अधूरा माना जाता है।

समय-समय पर सोशल मीडिया पर बंगालियों के खान-पान और हिंदू त्योहारों के दौरान मांसाहार को लेकर बहस छिड़ती रहती है। लेकिन, इस समुदाय के लिए यह उसकी संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप है।

जब से भाजपा ने बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत की है और मुख्य विपक्ष के रूप में उभरी है, तृणमूल कांग्रेस का उसके खिलाफ मुख्य हथियार उसके "बाहरी" होने का नैरेटिव रहा है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेताओं ने भाजपा को बंगाल में एक ऐसी "बाहरी" ताकत के रूप में पेश करने की कोशिश की है, जो राज्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को नहीं समझती।

तृणमूल ने कई राज्यों में भाजपा सरकारों द्वारा कई प्रकार के मीट, जैसे बीफ आदि पर लगाए गए प्रतिबंधों का मुद्दा उठाया है और दावा किया है कि सत्ता में आने पर यह पार्टी बंगालियों के खान-पान पर भी सख्ती कर सकती है। बनर्जी ने बार-बार भाजपा पर "खाद्य नियंत्रण की राजनीति" करने का आरोप लगाया है और चेतावनी दी है कि अगर वे सत्ता में आए तो राज्य में मछली और मांस पर प्रतिबंध लगा देंगे। ज्ञातव्य है कि बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा था कि बंगाल में मांस की खुलेआम बिक्री पर रोक लगा दी जाएगी। ममता बनर्जी ने सिन्हा के बयान को लेकर कहा है कि "वे बंगाल में मछली और मांस पर प्रतिबंध लगा देंगे, (जबकि) बंगाल मछली और चावल पर ही जीवित है।"

राष्ट्रदूत हिन्दु संयुक्त परिवार की ओर से सोमेश शर्मा द्वारा ज्वाईन्ट मीडिया, आजाद मार्ग, मैन रोड, आयड, उदयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 57928/93 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513 कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371 अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908